पाँचवा-स्तम्भ

40 CUTS International 1983-2023

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 24 , अंक 3/2023

अल्ट्रा-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ: पैक्ड खाद्य पदार्थों में मौजूद वसा, चीनी व नमक जैसी चीजों के बारे में जानकारी जरूरी

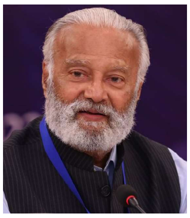

देखने में आ रहा है कि आजकल पोषण से अधिक अन्य सुख सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। जिससे शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में भी मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा जैसे गैर-संचारी रोग बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे की कमी के चलते ऐसे रोग तेजी से फैल रहे हैं।

इस बारे में किए गए कई अध्ययन बताते हैं कि भारत में करीब 60 फीसदी मौतों का कारण गैर संक्रामक बीमारियां हैं। ज्यादा मात्रा में वसा, शुगर और नमक इन बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। यह पदार्थ ज्यादातर अल्ट्रा-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और ज्यादातर पैकेटबंद खाद्य पदार्थों के रूप में उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं।

अल्ट्रा-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ ऐसे खाद्य उत्पाद हैं, जिनको अधिक मात्रा में प्रसंस्कृत किया जाता है और उनमें अतिरिक्त अवयव मिलाए जाते हैं। ये पदार्थ औद्योगिक प्रसंस्करण के कई चरणों से गुजरते हैं, जिनमें अक्सर रासायनिक तत्व, कृत्रिम स्वाद, रंग,

उपभोक्ताओं के हित में है 'फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग'

अस्वास्थ्यकारी वसा और मिठास शामिल होते हैं। इन खाद्य पदार्थों में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है। इसलिए इनसे मोटापा, हृदय रोग और मधुमेह जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

शहरी हो या ग्रामीण उपभोक्ता, उन्हें ताजे फल, सब्जियां, मोटा अनाज और तरल प्रोटीनयुक्त संतुलित आहार के बारे में जागरूक करना बहुत आवश्यक है। इस बारे में जानकारी होने पर वे अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकेंगे और सही पोषण से शारीरिक क्षमता को बढ़ाकर बीमारियों से बच सकते हैं। पैकेटबंद खाद्य पदार्थों में वसा, शुगर, नमक तथा स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद अन्य वस्तुओं की अधिकतम मात्रा के मानक दुनियाभर के कई देशों में तय है।

मानकों से ज्यादा मात्रा होने पर पैकेट के ऊपरी भाग (फ्रंट ऑफ पैक) पर 'अनहेल्दी' जैसा चेतावनी लेबलिंग एक प्रभावी उपाय है, जो उपभोक्ताओं को स्वस्थ विकल्प चुनने में सहायता करती है। यह स्पष्ट, प्रतीकात्मक और मानकीकृत लेबलिंग प्रणाली उपभोक्ताओं को उनके आहार संबंधी उद्देश्यों के अनुरूप, उत्पादों की तुलना करने और चयन करने में सहायक होती है।

यह बात समझनी होगी कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक जगरूकता अभियान की सख्त जरूरत है। इस तरह के अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संगठनों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

चेतावनी लेबल न केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं, बल्कि सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों, विशेष रूप से बुजुर्गों, युवाओं और अशिक्षित लोगों को भी जानकारी देने एवं स्वस्थ विकल्प चुनने में मदद करने के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लेबल दृश्य संकेतों के रूप में भी काम करते हैं, जो उपभोग से जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में उपभोक्ता को बताते हैं।

चिकित्सकों और वैज्ञानिकों की भी राय है कि भारत को वैश्विक मानकों के अनुसार फ्रंट ऑफ पैक चेतावनी लेबल को अपनाना चाहिए। यह न केवल गंभीर बीमारियों को रोकने के लिए जरूरी है, बल्कि विदेशों तक तेजी से बढ़ते खाद्य बाजार के बेहतर भविष्य के लिए भी फायदेमंद है।

वैश्विक विस्तार के लिए भारतीय खाद्य उद्योग के साथ ही भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) भी भारतीय हितों को देखते हुए फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग को अपनाना चाहेंगे।

प्रदीप एस महता
महामंत्री, कट्स इंटरनेशनल
(रा. प., 07.07.2023)

इस अंक में...

- पीएम फसल बीमा योजना में घपला 3
- सालों से प्रतिनियुक्ति पर जमे हैं अफसर 4
- उधारी से खुशियों का घी पिला रही सरकार ... 7
- भूजल दोहन से हिलने लगी है पृथ्वी की धुरी .. 9
- उद्यमिता में बढ़ रही महिलाओं की रुचि 10

‘अंकटाड’ के समर्थन से ‘कट्स’ द्वारा ग्लोबल वेबीनार आयोजित

वैश्विक उपभोक्ता संरक्षण को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण

‘अंकटाड’ के समर्थन से ‘कट्स’ इंटरनेशनल द्वारा नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल वेबीनार में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र के संगठन ‘अंकटाड’ की महासचिव, रेबेका ग्रिनस्पैन ने उपभोक्ता संरक्षण के मुद्दों को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाने और आने वाले समय में जी20 के फोरम पर इसके लिए विशेष बैठकें आयोजित किए जाने की पैरवी की है।

ग्रिनस्पैन ने पुरजोर तरीके से कहा कि आने वाले वर्षों में जी20 की शिखर बैठकों के साथ उपभोक्ता शिखर सम्मेलन भी आयोजित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रसार और स्थाई बदलाव जैसी चुनौतियों के व्यापक परिदृश्य में उपभोक्ता संरक्षण की चिंताओं को सक्रिय रूप से देखने और उनका समाधान निकालने की जरूरत है।

इस वेब परिचर्चा में सिविल20 के प्रधान समन्वयक (शेरपा) विजय केलकर--. नाम्बियार ने जोर देते हुए कहा कि हालांकि उपभोक्ता आर्थिक गतिविधि भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण है, लेकिन यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि इन गतिविधियों का प्राथमिक लक्ष्य जीवन की स्थायी गुणवत्ता की सुरक्षा, रख-रखाव और वृद्धि होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक ढंग से काम करने वाले बाजारों में उत्पादकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच प्रभावी सहयोग चलता रहता है, पर वैश्विक स्तर पर बाजार की असमानताओं और कमजोरियों को देखते हुए मजबूत उपभोक्ता संरक्षण उपायों की आवश्यकता है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में ‘कट्स’ इंटरनेशनल के महामंत्री प्रदीप एस महता ने 1999 में वित्तीय मुद्दों पर चर्चा हेतु मंच के रूप में अपनी स्थापना से लेकर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच बनने तक जी20 के विकास को रेखांकित किया।

उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में ठोस बदलाव की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इस विषय में हालांकि जी20 के ढांचे के भीतर चर्चा की गई है लेकिन वैश्विक परिस्थितियों में उतार-चढ़ाव के कारण इस पर ध्यान कम हो गया है। उन्होंने भारत के बाद अगले वर्ष ब्राजील में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के एजेंडे में उपभोक्ता संरक्षण को बहाल करने पर बल दिया।

ब्राजीलिया उपभोक्ता संरक्षण संस्थान (आईडीईसी) में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के निदेशक इगोर रोड्रिग्स ब्रिटो ने कहा कि ब्राजील में अगले जी20 शिखर सम्मेलन में उपभोक्ता संरक्षण के लिए एकजुट होने पर उपभोक्ता संगठनों की सामूहिक आवाज गूंजेगी। परिचर्चा में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के अनेक वक्ताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया और कहा कि वैश्विक स्तर पर बाजार की असमानताओं को देखते हुए उपभोक्ता संरक्षण का मुद्दा महत्वपूर्ण है।

विकसित करनी होगी ‘सतत् उपभोग की जीवनशैली एवं संस्कृति’

सतत् उपभोग की जीवन शैली एवं संस्कृति विकसित करने हेतु संचालित परियोजना के तहत 25 अगस्त 2023 को राजगढ़, चूरू में एक हित धारक संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन ‘कट्स’द्वारा ग्रामीण विकास समिति लीलकी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।

कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष रजिया गहलोत ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि नगर पालिका द्वारा क्षेत्र में 36 हजार पौधे लगाने का काम प्रगति पर है। इससे पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। जीवन शैली में सुधार कर सतत् उपभोग को बढ़ावा देने में सभी की भागीदारी आवश्यक है।

‘कट्स’ के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी अमर दीप सिंह ने बताया कि सतत् उपभोग व उत्पादन के विषय में भारत में खासतौर पर राजस्थान में बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। आज वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग करने के तरीकों में बदलाव आने से पर्यावरण एवं नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए ‘कट्स’ विगत कई वर्षों से इस परियोजना का संचालन कर रहा है। उन्होंने कहा सभी हित धारकों को साथ में मिलकर कचरे से मुक्ति, पर्यावरण में सुधार लाने, जल स्तर को बढ़ाने, जैविक खेती अपनाने जैसे काम करने होंगे।

कार्यक्रम में आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ.पवन शर्मा ने खान-पान में सुधार लाने और घरों में औषधीय पौधे लगाने, केमिकल से उपजे अन्न, फल व सब्जियों का उपयोग नहीं करने की सलाह दी। हेल्थ इंडिया सोसायटी के अध्यक्ष समर सिंह ने जैविक खेती को अपनाने एवं राजेन्द्र सिंह शेखावत ने प्लास्टिक के उपयोग से हो रहे नुकसान के बारे में बताया। कार्यक्रम में 50 से अधिक स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, मीडिया प्रतिनिधियों और पर्यावरणविदों आदि ने सक्रिय रूप ने भाग लिया।

फसल बीमाः किसान परेशान क्यों?

फसल बीमा योजना किसान के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। केंद्र व राज्य सरकार बीमा कंपनी में बीमा प्रीमियम की राशि जमा कराती है। किसानों से नाममात्र की राशि ली जाती है। राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि जब तक बीमा कंपनी को जमा नहीं कराती, बीमा कंपनी किसानों को क्लेम नहीं देती।

बीमा प्रीमियम किसानों के केसीसी खातों से काटने के बाद, उनके क्लेम बैंक खातों में जमा नहीं करने की भी शिकायतें हैं। बीमा कंपनियों ने अपने फायदे के लिए इस योजना में कई पेंच डाल रखे हैं। अभी तक प्रदेश के किसानों को पिछले साल की खरीफ और रबी की फसल का क्लेम नहीं मिला, जबकि इस साल खरीफ की बुआई के साथ किसान अपने हिस्से का प्रीमियम देकर बीमा करवा चुके हैं। केंद्र व राज्य सरकारों को योजना की खामियों को दूर कर प्रबंधन को मजबूत करना होगा। *(रा.प., 05.07.23)*

पीएम फसल बीमा योजना में घपला

राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों, कृषि व राजस्व विभाग के कार्मिकों और बीमा कंपनी एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस के स्तर पर लाखों हेक्टेयर खेतों के क्लेम फर्जी तरीके से उठा लिए गए।

फिलहाल 2025 से ज्यादा किसानों के साथ फर्जीवाड़ा होने के दस्तावेज सामने आए हैं। वहीं, 2500 अन्य किसान घपले की आशंका से चिंतित हैं। जो भी किसान अपना खसरा ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, उनका विवरण आ रहा है कि उनका क्लेम उठ चुका है। अकेले बाड़मेर व जैसलमेर जिले के 8 गांवों में ही 2000 खेतों का 300 करोड़ रुपए का क्लेम उठा लिया गया। किसानों को आशंका है कि खेतों में फर्जी हिस्सेदार बना दिए, वे इस रिकार्ड की आड़ में उनसे खेत ही न छीन लें। राज्य सरकार अब हरकत में आई है और सीएमओ के निर्देश पर हाईपावर जांच कमेटी गठित की गई है। *(दै.भा., 26.08.23, 28.08.23)*

अल्पसंख्यक संस्थानों में घोटाला

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति के घोटाले का मामला सामने आया है। इसमें फर्जी अल्पसंख्यक संस्थानों और फर्जी छात्रों के जरिए अब तक हजारों करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का अंदेशा है। शुरुआती जांच में 100 जिलों के 1572 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में से 53 फीसदी संस्थान फर्जी पाए गए।

यह संस्थान या तो अस्तित्व में ही नहीं है या लंबे समय से बंद हैं। इनमें ज्यादातर मदरसे हैं। इन 830 फर्जी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को पिछले पांच सालों में करीब 145 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इन सभी संस्थानों के खातों को फ्रीज कर दिया है और मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी गई है। देश में 1.80 लाख अल्पसंख्यक संस्थान हैं। इन संस्थानों के जरिए 22 हजार करोड़ की छात्रवृत्ति दी गई है। सभी संस्थानों की जांच की जाए तो हजारों करोड़ का फर्जीवाड़ा उजागर हो सकेगा। *(रा.प., 20.08.23)*

अटल भूजल मिशन में गड़बड़झाला

राज्य में गिरते भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए केंद्र के सहयोग से एक हजार करोड़ रुपए के बजट से अटल भूजल मिशन चलाया जा रहा है। मिशन में इंजीनियर फर्मों से मिलीभगत कर उपकरणों की खरीद में जमकर गड़बड़झाला कर रहे हैं। विभाग में हुई 1144 रेनगेज की दो करोड़ रुपए में खरीद में यह सामने आया है।

इंजीनियरों ने ग्राम पंचायतों में लगाए गए रेनगेज को 6 गुना ज्यादा दर पर खरीदा है। फर्म को आनन-फानन में पूरा भुगतान हुआ तो मामले का खुलासा हुआ। अब भू-जल विभाग के इंजीनियर अपने तर्कों से 6 गुना ज्यादा दरों पर की गई खरीद को जायज ठहराने में लगे हैं। मध्यप्रदेश में अटल भू-जल मिशन के तहत एक रेनगेज की खरीद 2599 रुपए में की गई है। जबकि राजस्थान में प्रति रेनगेज की खरीद 6 गुना यानी 16 हजार रुपए में की गई और फर्म को करीब दो करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। *(रा.प., 10.09.23)*

जल जीवन मिशन में घोटाला

प्रदेश में जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट में अफसरों की शह पर अनुबंधित कंपनियों द्वारा जमकर किए गए भ्रष्टाचार की पोल खुलती जा रही है। कई जगह काम पूरा हुए बिना, तो कई जगह काम किए बिना ही करोड़ों का भुगतान कर दिया गया। कई जगह लोहे की जगह प्लास्टिक के पाइप बिछा दिए गए।

अब अभियंता खुद को बचाने में जुटे हैं और खुद ही घटिया काम का भंडाफोड़ कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट में सारी जानकारी दी थी और रिपोर्ट में जलाशयों के स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त होने व जनहानि की आशंका तक जताई थी। बावजूद उच्चाधिकारी व नेता कंपनियों को फायदा पहुंचाने में जुटे रहे। अब गोविन्दपुरा बांसडी, राजावास, अमरसर जैसे कई गांवों में हुई गड़बड़ियों की पोल खुलती जा रही है। उच्चस्तरीय जांच कब होगी, पता नहीं? *(रा.प., 06.07.23)*

गरीबों के गेहूं का धणीधोरी कौन?

प्रदेश की राजधानी जयपुर में उचित मूल्य की दुकानों पर आर्थिक रूप से कमजोर तबके को वितरण के लिए पहुंचने वाले गेहूं की धांधली सरेआम हो रही है। विभाग के जिम्मेदार पूरे मामले से अनजान है। प्रबंधन की जिम्मदारी देख रहे राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के ट्रांसपोर्टर की ओर से सरकारी अनाज के वितरण में अनियमितता सामने आई है।

टोंक रोड ग्लास फैक्ट्री स्थित एफसीआई गोदाम से सरकारी गेहूं लेकर ट्रक रवाना होने के बाद शहर तक आने में ही ट्रक के वजन में 100-150 किलो तक की कमी हो जाती है। गौरतलब है कि एफसीआई गोदाम से ट्रक की तुलाई होती है। उसके बाद वह संबंधित उचित मूल्य दुकान पर वितरण के लिए जाता है। लेकिन जब उचित मूल्य दुकानदार पुनः ट्रक का वजन कराता है तो वजन कम निकलता है। बीच में गेहूं कहां कम हो जाता है? मामले में विभाग ने अब नागरिक आपूर्ति प्रबंधक से जांच रिपोर्ट मांगी है। *(रा.प., 20.09.23, 23.09.23)*

'आधार' से पकड़ी योजनाओं में चोरी

तकनीक के इस्तेमाल से 312 सरकारी योजनाओं में धन की लूट रोकने में केंद्र सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है। यह सब संभव हुआ है जनधन-आधार-मोबाइल यानी जैम ट्रिनिटी स्कीम से। अब तक सरकार ने 312 सरकारी योजनाओं में 2.73 लाख करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी है।

सरकार ने अब तक 312 योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में 29 लाख 84 हजार 412 करोड़ रुपए भेजे हैं। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जोड़े जाने से कागजों में हेरफेर कर जरूरतमंदों का हक डकारने पर अंकुश लगा है। तकनीक से फर्जीवाड़े को पकड़कर योजनाओं के लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने में बड़ी कामयाबी मिली है। तकनीक से फर्जी एलपीजी कनेक्शन, फर्जी राशन कार्ड, मनरेगा के फर्जी जॉब कार्ड जैसी कई अन्य योजनाओं में गड़बड़ियों की पोल खुली और धनराशि की लूट बंद हुई। *(रा.प., 17.07.23)*

प्रदेश में खनिज संपदा का अवैध खनन

प्रदेश में खनिज संपदा को लूटा जा रहा है और अफसर तमाशा देख रहे हैं। हर साल अवैध खनन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वर्ष 2015-16 से तुलना करें तो कुछ साल पहले तक अवैध खनन 169 फीसदी बढ़ गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में यह परेशान करने वाली हकीकत सामने आई है।

सबसे ज्यादा गंभीर तथ्य तो यह है कि पट्टेशुदा खनन क्षेत्र से सटे हिस्से में अवैध तरीके से खुदाई चलती रही लेकिन खनिज विभाग ने पुख्ता एक्शन नहीं लिया। कैग की रिपोर्ट में दांतारामगढ़, कोटपूतली, नीम का थाना, राजगढ़ व परबतसर में खनन क्षेत्रों की जांच की गई है, लेकिन विभाग ने सैंपल ऑडिट ही नहीं की और केवल दिखावटी काम करते गए। जानकारों का कहना है कि प्रदेशभर में जांच हो तो कई गुना राजस्व का नुकसान होने की स्थिति बनेगी। *(रा.प., 29.08.23)*

चिरंजीवी योजना धरातल पर फेल

सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बदलाव करते हुए प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी है। सरकार का दावा है कि सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी व आईपीडी से लेकर हर चिकित्सा राज्य के लोगों के लिए निःशुल्क है।

निजी अस्पतालों में योजना का असल फायदा गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को ही मिल रहा है। यह सुविधा केवल आईपीडी मरीजों के लिए है। निजी अस्पताल में भर्ती होने पर पहले हजारों रुपए परामर्श शुल्क व जांचों में खर्च हो जाते हैं। चिरंजीवी पॉलिसी में स्पष्टता का अभाव होने की वजह से निजी अस्पताल योजना को अपने अस्पताल में लागू करने के इच्छुक भी कम है। *(रा.प., 20.09.23)*

मेडिकल कॉलेजों में खरीदारी में गड़बड़ी

प्रदेश में बन रहे नए मेडिकल कॉलेजों में हर सामान की खरीद में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, धौलपुर के लिए खरीदे गए एक ही तरह के सामान में लाखों रुपए का अंतर है। भीलवाड़ा में जहां प्रिंसिपल टेबल 1 लाख 20 हजार में खरीदी, वहीं चूरू में यह 3 लाख 30 हजार रुपए में खरीदी गई।

इसी तरह और भी कई सामानों की खरीद में अनियमितता हुई है। झालावाड़ में भी कई गड़बड़िया सामने आई है। करौली, दौसा व अलवर के मेड़िकल कॉलेजों में भी फर्नीचर की खरीद में नियमों को दरकिनार कर चहेती फर्म को लाभ पहुंचाने का मामला सुर्खियों में है। *(दै.भा., 23.07.23)*

फर्जीवाड़ा कर अपात्रों ने उठाया लाभ

आमजन को राहत देने के लिए शुरू की गई राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में विभिन्न विभागों के कार्मिकों ने फर्जीवाड़ा कर ऐसे लोगों का इलाज करा लिया जो योजना के तहत पात्रता ही नहीं रखते थे। कार्मिकों ने सास-ससुर को माता-पिता बताकर तो किसी ने दोस्त को भाई बताकर इलाज करा क्लेम उठा लिया।

ऐसी कई गड़बड़ियों के मामले जनआधार से मिलान के बाद विजिलेंस टीम ने विभिन्न अस्पतालों से जुटाए हैं। आरजीएचएस ने कार्रवाई करते हुए करीब छह हजार कार्ड ब्लॉक कर दिए। लेकिन कुछ महीने ही कार्ड ब्लॉक रहे इसके बाद मामला जब सीएमओ तक पहुंचा तो अधिकारियों को निर्देश मिले कि सभी कार्डों को अन-ब्लॉक किया जाए। इसके बाद सभी कार्ड अन-ब्लॉक कर दिए गए। *(दै.भा., 01.08.23, 17.09.23)*

कन्यादान योजना में मिली गड़बड़ी

जैसलमेर के तीन ब्लॉक में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के 1.30 करोड़ रुपए हड़पने का मामला अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एसीबी में दर्ज कराया है। सहायक अधिकारी पूरणमल वर्मा के नेतृत्व में एक टीम ने जैसलमेर में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि में इस योजना के तहत किए भुगतान की जांच की।

जैसलमेर ब्लॉक में 254, सांकड़ा में 255 और सम में 162 खातों में 2.96 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इनमें 288 लाभार्थियों की नमूना जांच में 1.24 करोड़ रुपए का अनियमित भुगतान ऑनलाइन फॉर्मों के साथ कूटरचित दस्तावेज कर किया गया था। जांच में 351 आवेदन ऐसे पाए गए, जिनका भुगतान सिर्फ एक बार एक ही खाते में हुआ। *(रा.प., 11.07.23)*

सालों से प्रतिनियुक्ति पर जमे हैं अफसर

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम भले ही बेरोजगारों को रोजगार देने में पीछे है, लेकिन यहां प्रतिनियुक्ति पर लगे अधिकारियों का खूब विकास हो रहा है। निगम में राज्य और दूसरे राज्यों से अधिकारी प्रतिनियुक्ति ले रहे हैं। कोलकाता सहित अन्य राज्यों के ये अधिकारी पांच साल से भी अधिक समय से निगम में जमे हुए हैं।

हैरानी की बात यह है कि इन अधिकारियों का बुलावा मूल विभाग से भी आ चुका है, लेकिन अधिकरी यहां से जाने को राजी नहीं हैं। मामले में पी.सी.किशन, शासन सचिव, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग का कहना है कि जो भी प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी लगे हैं, उनके कामकाज को देखा जा रहा है। खामियां पाई गई तो उन्हें रिलीव कर दिया जाएगा। *(रा.प., 09.08.23)*

जरूरी है भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रयास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार का प्रभाव सबसे अधिक गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर पड़ता है। भ्रष्टाचार संसाधनों और बाजार मूल्यों को प्रभावित करता है। इससे लोगों के जीवन की गुणवत्ता कम होती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सामूहिक प्रयास आवश्यक है।

कोलकता में आयोजित भ्रष्टाचार विरोधी जी-20 की मंत्रिस्तरीय बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में 'भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस' की सख्त नीति है। उन्होंने कहा कोरोना वायरस काल में गरीबों के लिए हमारी मुफ्त राशन योजना की दुनिया भर ने सराहना की है। कोरोना अवधि के दौरान हमारी सरकार ने यह तय किया था कि कोई भी खाली पेट नहीं सोएगा।

(रा.प., 13.08.23)

भारत में कम हो रही है गरीबी

सयुंक्त राष्ट्र ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश, भारत द्वारा गरीबी को खत्म करने में प्राप्त की गई उल्लेखनीय उपलब्धियों की तारीफ की है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही जारी संयुक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि खासतौर पर भारत में 15 साल में 41 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005-06 में भारत में 64.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से जकड़े हुए थें। 2015-16 में यह संख्या घट कर 37 करोड़ और 2019-21 में यह 23 करोड़ रह गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सबसे गरीब राज्यों और वंचित जाति समूहों में गरीबी की गिरावट सबसे तेज दर्ज की गई है।

(रा.प., 12.07.23)

जम्मू-कश्मीर में युवा ला रहे बदलाव

अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में महिलाएं और युवा नया बदलाव ला रहे हैं। खास बात यह है कि अब यहां के बाशिंदों ने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। टेक्नोलॉजी की मदद से कश्मीरी कालीन और पश्मीना शॉल बनाने के काम में तेजी आई है।

जी20 शिखर सम्मेलन

विश्व में सभी के कल्याण की कामना के साथ संपन्न

भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना के साथ संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार व सभी के कल्याण की कामना के साथ संपन्न हो गया। दुनियाभर में भारत की भूमिका को बेहद सफल माना जा रहा है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि तैयार संयुक्त घोषणा-पत्र के प्रत्येक पैराग्राफ पर सभी ने अपनी 100 प्रतिशत सहमति जताई।

राजधानी दिल्ली में 9 एवं 10 सितम्बर को हुए समिट में अमेरिका से लेकर फ्रांस तथा कनाड़ा से लेकर जापान तक तमाम देश शामिल हुए और भारत के प्रस्तावों को एक मत के साथ अपनी रजामंदी दी। इंडिया, मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर डील, अफ्रीकी यूनियन को जी 20 में नए स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने और रूस-यूक्रेन युद्ध को साधते हुए सर्वसम्मति बनाना सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। भारत की महत्वपूर्ण सफलता और अपनी कूटनीति का लोहा मनवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को प्रेसिडेंसी गेवल (कमान) सौंपते हुए उम्मीद जताई कि अगले साल ब्राजील के नेतृत्व में जी20 साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगा।

(रा.प. एवं दै.भा., 10.09.23, 11.09.23)

अब महिलाएं तरह-तरह के इनोवेटिव तरीकों से कालीन और पश्मीना शॉल बना रही हैं। नए-नए स्टार्टअप खड़े हो रहे हैं। डिजाइनर शाहनवाज सोफी बताते हैं कि पहले डिजाइन बनाने में 3-4 महीने लग जाते थे लेकिन अब सॉफ्टवेयर से काम तेज हुआ है। कालीन, पश्मीना शॉल और क्रिकेट बैट आदि का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। करीब 90 प्रतिशत सामान विदेश जाता है। अब तो बच्चियां भी तरह-तरह के इनोवेटिव बिजनेस कर रही हैं।

(दै.भा., 03.08.23)

गरीबी से बाहर निकले लोग

संयुक्त राष्ट्र के बाद अब नीति आयोग ने भी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में वर्ष 2015-16 में 24.85 प्रतिशत लोग गरीब थे, जो वर्ष 2019-21 में कम होकर 14.96 प्रतिशत रह गए। पिछले पांच साल में 23.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि में गरीबों की संख्या में 9.89 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में सबसे तेज गिरावट आई है और यह 32.59 प्रतिशत से घटकर 19.28 प्रतिशत रह गई है। जबकि शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65 प्रतिशत से घटकर 5.27 प्रतिशत रह गई है। इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट आई है। नीति आयोग ने कहा कि स्वच्छता, पोषण अभियान, वित्तीय समावेशन, पेयजल और बिजली तक पहुंच में सुधार ने गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(रा.प., 18.07.23)

चुनौतियों से निपटने को बनाएंगे फंड

बी20 के सालाना शिखर सम्मेलन में बिजनेस लीडर्स ने एक विशेष फंड बनाने की पेशकश की है। इसमें हर कंपनी को अपने मुनाफे का 0.2 फीसदी देना होगा। इसका इस्तेमाल सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल करने में किया जाएगा। यह प्रस्ताव टाटा सन्स के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने दिया। यह देश के सीएसआर फंड जैसा है, जिसमें सूचीबद्ध कंपनियों को शुद्ध मुनाफे का 2 प्रतिशत देना होता है।

इस प्रस्ताव का एक कारण ये है कि संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एसडीजी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया के देश महज एक तिहाई गोल्स तक सीमित हो गए हैं। कुछ जरूरी लक्ष्यों जैसे गरीबी, भुखमरी, और जलवायु परिवर्तन पर काम अब तक संतोषजनक नहीं रहा है। सम्मेलन में कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के सीईओ उदय कोटक ने कहा कि यह फंड जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन और जैव विविधता जैसे क्षेत्रों में भी उपयोग किया जाएगा। सम्मेलन में दुनियाभर के 1400 से ज्यादा बिजनेस लीडर्स ने 54 विषयों पर प्रस्ताव बनाया है।

(दै.भा., 29.08.23)

ग्राम गदर जनमत सर्वेक्षण- 2023

जैसा कि विदित है, 'कट्स' अपने भित्तीपत्र 'ग्राम गदर' के माध्यम से सरकार की वर्तमान कार्यप्रणाली, भ्रष्टाचार, राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं और महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दों की वास्तविक स्थिति जानने के उद्देश्य से समय-समय पर सर्वेक्षण कराता रहा है। इस बार किए गए सर्वेक्षण में राज्य के ज्वलंत मुद्दों के साथ-साथ आज की तारीख में राज्य में चुनाव हों तो क्या स्थिति बनेगी, इस पर भी आम जनता से रायशुमारी की गई।

इसके लिए राजस्थान के विभिन्न जिलों के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कार्यरत 'कट्स' की सहयोगी संस्थाओं, कार्यकर्ताओं और वॉलन्टियरों को सर्वे फार्म भिजवाकर उन्हें अपने क्षेत्र के विभिन्न लिंग, जाति और समुदायों के लोगों से चाहे गए प्रश्नों के उत्तर सर्वे में भरवाकर पुन: प्रेषित करने को कहा गया। राज्य के समस्त 33 जिलों की अधिकांश पंचायत समितियों में स्थित कार्यकर्ताओं को भेजे गए परिपत्रों में से संस्था को 23 जिलों की पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों से 479 सर्वे परिपत्र प्राप्त हुए। सभी सर्वे प्रपत्र 'कट्स' कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीण स्तर पर सीधी बातचीत के आधार पर पूर्ण किए गए हैं। विश्लेषण करने पर मुख्य तौर पर निम्न परिणाम सामने आए हैं।

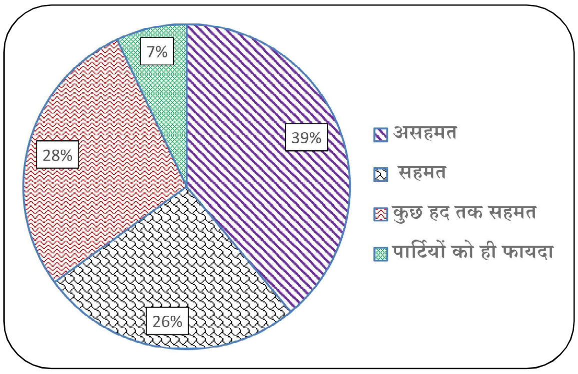

एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या चुनाव से पूर्व किसी भी मौजूदा सरकार या चुनाव लड़ रही किसी भी पार्टी द्वारा की गई मंहगाई राहत/मुफ्त की घोषणाओं से सहमत है। इस पर 39 फीसदी लोगों ने अपनी असहमति व्यक्त की वहीं 26 फीसदी लोगों ने अपनी सहमति दी और 28 फीसदी ने कुछ हद तक ही इसे सही ठहराया। करीब 7 फीसदी से अधिक लोगों का मानना है कि मुफ्त की घोषणाओं से चुनाव में पार्टियों को ही फायदा होता है। निर्धन व कमजोर वर्ग को ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता।

सर्वे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सर्वाधिक 44 फीसदी लोगों का मानना है कि मौजूदा राज्य सरकार पूर्व में किए गए चुनावी वादों को पूरा करने में खरी नहीं उतरी। मात्र 23 फीसदी लोगों ने ही माना है कि सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा किया है जबकि 25 फीसदी लोगों का मानना है कि सामान्य रूप से सरकार चुनावी वादों को पूरा करने में सफल रही है। करीब 8 फीसदी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

इसी क्रम में लोगों से पूछा गया क्या इस बार मौजूदा पार्टी की सरकार के दोबारा आने की संभावना है? इस पर 32 फीसदी ने वर्तमान सरकार के फिर से वापस आने और 33 फीसदी ने वर्तमान सरकार के दोबारा नहीं आने की बात कही है। करीब 35 फीसदी लोगों ने इस बारे में अपनी राय प्रकट नहीं की।

सर्वे में वर्तमान सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को लाभप्रद मानते हुए 43 फीसदी लोगों ने इसे पर हामी भरी, जबकि करीब 39 फीसदी लोगों ने इसे कुछ हद तक लाभप्रद माना है। करीब 15 फीसदी लोगों का कहना है कि उन्हें स्वास्थ योजनाओं का सही लाभ नहीं मिल पाया।

एक अन्य प्रश्न में लोंगों से पूछा गया कि क्या केन्द्र सरकार की योजनाओं के लिए प्रदेश को आवंटित धन राशि का सही उपयोग हुआ? इस प्रश्न पर 26 फीसदी लोगों ने 'हां' में तो 30 फीसदी ने 'नहीं' में जवाब दिया। करीब 44 फीसदी लोगों को तो इन योजनाओं की पूरी जानकारी तक नहीं है।

सर्वेक्षण में पूछे गये प्रश्नों से यह भी आया सामने

1. इस बार आप प्रदेश के विधान सभा चुनाव में पार्टी देखकर वोट देना पसंद करेंगे या प्रत्याशी देखकर?
   पार्टी देख कर 23% प्रत्याशी की जाति देख कर 05 % प्रत्याशी की योग्यता देख कर 72%
2. इस बार आपकी नजर में राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या क्या है?
   भ्रष्टाचार 21% महंगाई 23% बेरोजगारी 27% कानून व्यवस्था 11% उत्तर नहीं 18%
3. वर्तमान में बढ़ती महंगाई का सबसे बड़ा कारण क्या है?
   भ्रष्टाचार 32 % योजनाओं की क्रियान्विति नहीं 21 % आर्थिक मंदी 20% काला बाजारी 20 % उत्तर नहीं 07%
6. क्या आप मानते हैं कि राज्य की वर्तमान सरकार सही दिशा में काम कर रही है ?
   हां 28 % नहीं 27 % ठीक-ठाक 35 % कोई राय नहीं 10 %

सर्वे में पूछा गया कि चुनाव के बाद आने वाली नई सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? तो इसके जवाब में ज्यादातर लोगों का मानना हैं कि सरकार चुनाव के समय किए गए वादों को समय पर पूरा करें जिससे आमजन को योजनाओं का समय पर सही लाभ मिल सके। लोग बेरोजगार होने की वजह से गांवों से पलायन नहीं करें इसके लिए कृषि को खास अहमियत दी जाए। गांव का युवा आज अपने गांव से पलायन कर शहरों की तरफ आकर्षित हो रहा है, जिससे कृषि का विस्तार सीमित होता जा रहा है। यह एक गंभीर समस्या है। इस समस्या का समाधान आवश्यक है। देश और प्रदेश के विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार न हो और इसके लिए समय-समय पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। सबसे बड़ी समस्या महंगाई ओर बेरोजगारी है। इसका हल निकाला जाना चाहिए।

प्रदेश में अब 10 संभाग और 50 जिले

प्रदेश में अब जिले 33 से बढ़कर 50 और संभाग 7 से बढ़कर 10 हो गए हैं। आजादी के बाद राज्य का यह सबसे बड़ा पुनर्गठन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि नए जिलों का गठन विकास, निवेश व कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिए किया गया है।

जयपुर के बिडला सभागार में आयोजित प्रदेशस्तरीय समारोह में 07अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूजा और हवन में आहुतियां दीं और विधिवत मंत्रोच्चार के बीच नए जिलों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वीसी के जरिए नए 17 जिलों में मंत्री-विधायक और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम से जुड़े और नए जिलों की आधार शिला रखी।

(रा.प.एवं दै.भा., 05.08.23, 08.08.23)

ऑर्गेनिक में नहीं होगा फर्जीवाड़ा

ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों के नाम पर अब फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने सभी परीक्षण सुविधाओं और प्रयोगशालाओं को सख्ती से निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है।

ऑर्गेनिक खाने-पीने की चीजों से छेड़छाड़ करने वालों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। इसके तहत बाजार में नकली उत्पाद लाने वालों को 2 से 10 साल की सजा तक हो सकती है। एफएसएसएआइ ने हाल ही में नकली ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक उत्पादों को प्रमाणित करने की आवश्यकता है। गलत ब्रांडिंग के लिए 3 लाख और भ्रामक विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है।

(रा.प., 06.07.23)

खर्च में इजाफा होने से लोग परेशान

कमरतोड़ मंहगाई ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले खर्च में लगातार हो रही बढ़ोतरी भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है।

एसबीआइ लाइफ इंश्योरेंस के फाइनेंशियल इम्यूनिटी स्टड़ी के मुताबिक, देश में 59 फीसदी लोग बढ़ती खाद्य महंगाई से परेशान हैं। वहीं 43 फीसदी लोगों ने माना है कि रोजाना खपत वाली चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी उनकी चिंता का प्रमुख कारण है। सर्वे में 36 फीसदी लोगों ने बढ़ते स्वास्थ्य खर्च, 35 फीसदी लोगों ने शिक्षा के खर्च में हुई बढ़ोतरी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। क्योंकि शिक्षा की महंगाई हर साल 11 से 12 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, वहीं इलाज हर साल 14 प्रतिशत की दर से महंगा हो रहा है। इसके अलावा 24 फीसदी लोगों को अपनी नौकरी खोने का भी डर सता रहा है।

(रा.प., 12.09.23)

डॉक्टर लिखें पर्चे पर जेनेरिक दवाएं

अब डॉक्टरों को मरीज के पर्चे पर जेनेरिक दवाएं ही लिखनी होंगी। पंजीकृत डॉक्टर इन दवाओं को साफ अक्षरों में लिखें। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) नई दिल्ली के नए नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं करने पर उनका लाइसेंस कुछ समय के लिए निलंबित हो सकता है।

केंद्र सरकार भी अनेकों बार जेनेरिक दवाएं लिखने का निर्देश जारी कर चुकी है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देशभर में संचालित केंद्रों पर जेनेरिक दवाएं मिलती हैं। देश में लोगों की कमाई में से बड़ी राशि सिर्फ स्वास्थ्य पर खर्च होती है। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं से 70 से 90 फीसदी तक सस्ती होती हैं। *(दै.भा., 15.08.23)*

अब गांवों में होंगे ज्यादातर अमीर

अगले 10 साल में देश में अधिक धनवान घरानों की संख्या 5 गुना बढ़ जाएगी। इस बढ़ोतरी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण भारत में होगा। प्राइस (पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी सिटीजन एनवायरनमेंट) द्वारा जारी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। दो करोड़ रुपए से अधिक सालाना कमाने वाले को सुपर रिच माना गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग तेजी से व्यावसायिक कृषि कारोबारों के साथ गैर कृषि कामों में लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उद्यमियों की बाढ़ सी आ रही है, जो नौकरियां दे रहे हैं और छोटे कारोबार खड़े कर रहे हैं। ऑक्सफेम इंटरनेशनल का भी अनुमान है कि भारत ने 2018 और 2022 के बीच हर दिन 70 करोड़पति बनाए हैं। इससे दुनिया का ध्यान भारत पर केंद्रित हुआ है। *(दै.भा., 06.07.23)*

भारत बनेगा दुनिया के विकास का इंजन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स देशों के 15वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आने वाले सालों में दुनिया के लिए विकास इंजन बनेगा। आज भारत दुनिया के लिए सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। जल्द ही 5 ट्रिलियन डॉलर (करीब 410 लाख करोड़ रुपए) की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

उन्होंने कहा भारत में जीएसटी और इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड़ लागू होने के बाद निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। इससे पहले, प्रिटोरिया हिंदू सेवा समाज के कार्यकर्ताओं और स्वामीनारायण संस्थान की स्थानीय इकाई सहित भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की।

(दै.भा., 23.08.23)

उधारी से खुशियों का घी पिला रही सरकार

चुनावी साल में प्रदेश में वित्तीय संकट की आहट सुनाई दे रही है। चुनावी फायदों को प्राथमिकता देकर राज्य सरकार उधारी से खुशियों का घी पिला रही है। राज्य हो या केंद्र बजट से बाहर योजनाओं पर खर्च करना आम बात हो गई है। विधानसभा हो या संसद अर्थव्यवस्था पर चर्चा ही नहीं होती।

चुनावी फायदे की योजनाओं और मुफ्त सामग्री बांट कर मतदाताओं को रिझाने पर पैसा ज्यादा खर्च किया जा रहा है। आंकड़ों में राजस्व और उधारी को देखा जाए तो अप्रेल से जुलाई तक वर्ष 2018 के मुकाबले मौजूदा वित्तीय वर्ष में राजस्व केवल 64 प्रतिशत ज्यादा आया, जबकि इसी अवधि में उधारी 106 प्रतिशत ज्यादा रही। पिछले सालों में उधारी का भार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मौजूदा सरकार के पहले साल में 6 माह में जो कर्जा लिया गया, उससे ज्यादा सरकार इस साल 4 माह में ले चुकी है। *(रा.प., 27.09.23)*

विद्युत उपभोक्ताओं का सशक्तीकरण

विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम 2020

सभी विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 के तहत 31.12.20 को विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 पारित किया है। इन नियमों के अंतर्गत भारत सरकार ने प्रावधान किया है कि वितरण कंपनियों द्वारा किसी प्रकार की अनावश्यक/जानबूझकर लोड शेडिंग नहीं की जाएगी।

इन नियमों के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 247 (आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं की श्रेणियों को छोड़कर) विद्युत आपूर्ति का अधिकार दिया गया है और यदि वितरण कंपनी जानबूझकर लोड शेडिंग का सहारा लेती है तो उपभोक्ताओं को वितरण कंपनी से क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने भी विभिन्न सेवाओं के लिए वितरण कंपनी द्वारा लिए जाने वाले अधिकतम समय के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं जिनमें कनेक्शन, डिस्कनेक्शन, रिकनेक्शन, शिफ्टिंग उपभोक्ता श्रेणी और लोड में परिवर्तन, बिल संबंधी सेवाएं और वॉल्टेज तथा बिल संबंधी शिकायतों का समाधान शामिल है। इन सेवाओं को प्रदान करने में किसी प्रकार का विलंब होने पर वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए आप अपने संबंधित डिस्कॉम की वेबसाइट पर देख सकते हैं। *(दै.भा., 18.08.23)*

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में होंगे नम्बर वन

राजस्थान सोलर के बाद अब विंड एनर्जी (हवा से बिजली) उत्पादन में भी देश में सबसे ऊपर होगा। यहां हवा से बिजली उत्पादन की क्षमता देश में सबसे ज्यादा आंकी गई है। केंद्र सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की स्टडी रिपोर्ट में यह तस्वीर सामने आई है।

राजस्थान का अभी तक सोलर एनर्जी पर फोकस रहा, विंड एनर्जी को सपोर्ट के रूप में ही देखते रहे। अब सरकार की विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए बड़े निवेशकों को लाने की तैयारी है। इससे सस्ती बिजली बनने की आस भी बंधी है। अक्षय ऊर्जा के दो ही मुख्य घटक हैं-सोलर व विंड एनर्जी। इन दोनों के लिए राजस्थान में जो संभावनाएं है उसके आधार पर काम होगा तो प्रदेश अक्षय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी)का स्किल कैपिटल बन जाएगा। *(रा.प., 21.07.23)*

खेतों में बिजलीः होगा संकट दूर

खेतों में फसल के साथ अब बिजली उत्पादन की भी तैयारी है। इससे बिजली संकट से जूझ रहे राजस्थान को कुछ राहत मिलने के आसार है। प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों ने 33 केवी जीएसएस के आसपास खेतों में छोटे सोलर प्लांट लगाने की योजना शुरू की है। किसानों को दिन में बिजली सप्लाई कर फसलों के लिए उनकी बिजली की मांग पूरी की जाएगी।

प्रदेश में सौर कृषि आजीविका योजना (एसकेएवाई) में 1 से 5 मेगावॉट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाने हैं। जोधपुर में पहले फेज में 2073 जीएसएस के आसपास करीब 6000 मेगावॉट क्षमता के प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पैदा होने वाली सौर ऊर्जा की सप्लाई किसानों को की जाएगी, जिससे डिस्कॉम को अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। *(दै.भा., 18.09.23)*

ट्रांसफार्मर की कमी ने उड़ाई नींद

विद्युत सप्लाई प्रबंधन में फेल होने के बाद बिजली महकमा अब ट्रांसफार्मर की कमी से जूझ रहा है। जयपुर डिस्कॉम में सिंगल और थ्री फेज के ट्रांसफार्मर की कमी के कारण किसान व अन्य उपभोक्ता परेशान है। हालात यह है कि जयपुर डिस्कॉम के 12 जिलों में करीब 5 हजार ट्रांसफार्मर जल चुके हैं।

इन्हें तय समय पर नहीं बदलने के कारण उपभोक्ताओं की नींद उड़ गई है। किसानों को सिंचाई के लिए समय पर पानी नहीं मिल रहा क्यों कि वहां बिजली सप्लाई बाधित है। डिस्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार 4 सितम्बर तक करीब तीन हजार ट्रांसफार्मर जले हैं। झालावाड़, अलवर, भरतपुर, करौली में आंकड़ा ज्यादा है। हालांकि कई जगह नए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए दूसरे जिलों से व्यवस्था की गई है। *(रा.प., 08.09.23)*

धरती की गर्मी से हो रही बिजली पैदा

अब पृथ्वी की ऊष्मा कैप्चर कर हर देश जियोथर्मल ऊर्जा का दोहन कर सकेगा। अब तक 30 देशों में करीब 400 बिजली संयत्र पृथ्वी की सतह से नीचे पैदा होने वाली भाप का इस्तेमाल करके बिजली पैदा कर रहे हैं, जिसमें कुल 16 गीगावॉट की क्षमता है। हाल ही जारी संयुक्त राष्ट्र की रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2023 में इसके संकेत मिलते हैं।

पृथ्वी का कोर यानी केंद्र का तापमान करीब 6000 डिग्री सेल्सियस है और इस तापमान पर पृथ्वी का केंद्र उतना ही गर्म है जितना कि सूर्य। इस तापमान से ऊष्मा आधारित ऊर्जा प्राप्त करने की संभावना होती है। हमारे पूर्वज भी जियोथर्मल एनर्जी की शक्ति से अपरिचित नहीं थे। भू-तापीयस संसाधनों का मानचित्रण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किया गया है। व्यापक अनुसंधानों के अनुसार, भारत में कुल 10 गीगावॉट भू-तापीय ऊर्जा क्षमता हो सकती है। *(रा.प., 28.08.23)*

प्रदेशवासियों को महंगी बिजली क्यों?

राजस्थान सोलर के बाद विंड एनर्जी में भी धाक जमा रहा है, मगर हकीकत यह है कि इस सस्ती बिजली का बड़ा फायदा प्रदेशवासियों को नहीं मिल रहा। यहां 17,500 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट है, लेकिन हमें केवल 4500 मेगावॉट ही सस्ती बिजली मिल रही है। यानी, 74 प्रतिशत सस्ती बिजली दूसरे राज्यों को सप्लाई हो रही है।

प्रदेश में सोलर पार्क विकसित करने वाली कंपनियों के फायदे के लिए बनाई गई अनुबंध शर्तों के कारण ऐसा हो रहा है। इस अनुबंध में राजस्थान डिस्कॉम को ज्यादा सौर ऊर्जा देने की बाध्यता नहीं है। गौरतलब है कि पिछले वर्षों में बिजली खपत 3.20 लाख यूनिट तक बढ़ गई है। ऐसे में अक्षय ऊर्जा की तुलना में महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। इससे प्रदेश में उपभोक्ताओं को महंगी बिजली सप्लाई की जा रही है। *(रा.प., 24.07.23)*

पूरी दुनिया के लिए खतरे की आहट

दुनिया की एक-चौथाई आबादी वाले 25 देश अत्यधिक जल संकट का सामना कर रहे हैं। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस के अनुसार पानी को लेकर गंभीर हालत से जूझते 25 देशों में भारत का स्थान 24वां है। रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया की आधी आबादी यानी 4 अरब लोग हर साल कम से कम एक महीने के लिए पानी की किल्लत झेलने को मजबूर हैं। वैश्विक स्तर पर 1960 के बाद पानी मांग दोगुनी से भी अधिक हो गई है।

पृथ्वी के 70 फीसदी हिस्से पर पानी होने के बावजूद विश्व में भूमिगत जल निरंतर कम हो रहा है। इसकी वजह है भूगर्भ से पानी का अत्यधिक दोहन। जिसके दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं। अमरीका के दक्षिणी-पश्चिमी एरिजोना, यूटा और कैलिफोर्निया प्रांतों में तो कई जगह मीलों लंबी दरारें उभर आई हैं। भूवैज्ञानिकों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार अब तक 169 मील लंबी दरारें या खाइयां बन चुकी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अमरीका में पिछले चार दशक में 10 में से 4 जोन पानी खींचने से इतने प्रभावित हुए हैं कि अब इसकी भरपाई संभव नहीं हैं।

(रा.प., 18.08.23, 14.09.23)

बनेंगे पेयजल उपभोक्ता सहायता केंद्र

जयपुर शहर में 563 करोड़ रुपए की लागत वाला बीसलपुर-पृथ्वीराज नगर पेयजल प्रोजेक्ट फेज प्रथम खास होगा। पहले चरण के तहत लाभान्वित होने वाली ढाई लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 50 हजार जल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। वहीं, निर्माण करने वाली फर्म ही दस साल तक इस प्रोजेक्ट का रख-रखाव करेगी।

प्रोजेक्ट की खास बात यह होगी कि सभी सात पंप हाउस पर उपभोक्ता सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। यह केंद्र उपभोक्ताओं की पेयजल संबंधी शिकायतों को दर्ज कर फील्ड इंजीनियरों को सूचना देगा। इससे तय समय पर पेयजल की समस्याओं का समाधान होगा। प्रोजेक्ट के तहत रंगोली गार्डन पेयजल परियोजना से 53 कॉलोनियों में जल कनेक्शन के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इस परियोजना से क्षेत्र की 32 हजार की आबादी को बीसलपुर का पानी मिलेगा।

(रा.प., 23.09.23)

जयपुर में लगेंगे पानी के नए स्मार्ट मीटर

शहर में 1.50 लाख से ज्यादा पानी के मीटर खराब है। ऐसे उपभोक्ताओं को लगातार औसत गणना के आधार पर बिल भेजे जा रहे हैं। विधान सभा में विधायक कालीचरण सराफ के एक सवाल के जवाब में यह स्थिति सामने आई। सरकार ने माना कि शहर में करीब 4.60 लाख मीटर है और इनमें से डेढ़ लाख मीटर खराब या बंद है।

गौरतलब यह है कि ऐसे में पानी उपभोग की सटीक गणना नहीं होने से इन उपभोक्ताओं को 15 हजार लीटर तक पानी मुफ्त मिलने की छूट नहीं मिल पा रही है। अब चुनावी साल के आखिरी महीनों में जलदाय मंत्री महेश जोशी ने बताया कि शहर में पानी के 15 हजार खराब मीटरों की जगह नए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

शेष एक लाख 50 हजार खराब मीटर को अमृत-2 परियोजना के तहत बदला जाएगा। इससे 15 हजार लीटर तक जल उपभोग वाले उपभोक्ताओं को बिल में छूट मिल सकेगी।

(रा.प., 18.07.23, 24.07.23)

प्रदेश में पिछड़ा हर घर नल कनेक्शन

प्रदेश के 12 जिलों में जल जीवन मिशन से हर घर जल कनेक्शन का काम बहुत पिछड़ गया है। पिछले चार साल में इन जिलों में 35 फीसदी काम भी नहीं हो पाया। जबकि प्रदेश में 41.15 फीसदी कनेक्शन हो चुके हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व जैसलमेर में अभी तक कुल घरों में से 20 फीसदी घरों में भी नल से पानी नहीं पहुंच रहा है।

ऐसे में महिलाओं को दूरदराज के इलाकों से सिर पर मटकी रखकर या बाल्टी से पानी लाना पड़ रहा है। जबकि जल जीवन मिशन की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तक ही है। माना जा रहा है कि यदि काम की गति नहीं बढ़ी तो केंद्र सरकार से 45 फीसदी मिलने वाली वित्तीय सहायता अटक जाएगी। *(दै.भा., 24.07.23)*

परियोजनाओं पर हो रही मशक्कत

जयपुर शहर में पानी के सहारे नेता चुनाव की नैया पार करने की जुगत में हैं। जलदाय मंत्री महेश जोशी शहर के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए धड़ाधड़ मंजूरी दे रहे हैं। जिससे चुनाव आचार संहिता लगने से पहले इन पेयजल परियोजनाओं का काम धरातल पर दिखाई देने लगे और जनता को सरकार की उपलब्धि बता सकें।

जलदाय विभाग की वित्त समिति ने मालवीय नगर की जगतपुरा पेयजल परियोजना के लिए 18.30 करोड़, मालवीय नगर गैटोर पेयजल परियोजना के लिए 14.68 करोड़ और श्याम नगर पेयजल परियोजना के लिए 8.19 करोड़ रुपए की मंजूरी भी जारी कर दी। इससे इन दोनों क्षेत्रों में रह रही करीब डेढ़ लाख की आबादी की पेयजल जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।

(रा.प., 21.08.23)

अत्यधिक भूजल दोहन से हिलने लगी है पृथ्वी की धुरी

साल 2000 की शुरुआत में पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने में कुछ अनियमितता देखी गई है। पृथ्वी का झुकाव पूर्व की ओर जाने लगा है। तभी से इसके कारणों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। एक शोध में पता चला है कि ध्रुवीय बर्फ और पर्वतीय ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने के कारण यह हुआ है।

अब हाल ही में इसका एक और बड़ा कारण पता चला है। बढ़ती आबादी की जरूरतों और सिंचाई के लिए भारी मात्रा में जमीन से पानी निकाला जा रहा है। इससे पृथ्वी की धुरी प्रभावित हुई है और इसके घूमने का संतुलन गड़बड़ाया है। दरअसल, जमीन से पानी तो निकाला जा रहा है लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो रही है। इससे जमीन अपने स्थान से खिसक सकती है।

इससे घरों व बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। वैज्ञानिकों का मत है कि इससे भूजल के स्रोत हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 1960 से 2000 के बीच दुनियाभर में जमीन से निकाले जाने वाले जल की मात्रा दोगुनी हो गई। हर साल करीब 75 ट्रिलियन गैलन पानी निकाला गया। इससे स्थिति गंभीर होती जा रही है। *(दै.भा., 11.07.23)*

उद्यमिता में बढ़ रही महिलाओं की रुचि

प्रदेश में महिलाएं अब उद्यमिकता के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उनका सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) में स्वामित्व बढ़ रहा है। प्रदेश में वर्ष 2021-22 में महिला स्वामित्व वाले 29500 एमएसएमई उद्योग थे जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 69,259 हो गए हैं।

यह सामने आ रहा है कि कोरोना काल के बाद से महिलाओं के कदम इस क्षेत्र में तेजी से बढ़े हैं। खासतौर पर बड़े शहरों के साथ ही गांवों से भी महिलाएं उद्यमी के तौर पर आगे बढ़कर इस क्षेत्र में अपना परचम फहरा रही हैं। पूरे देश में राजस्थान इस मामले में सातवें स्थान पर हैं। महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई में देश में पहला नंबर महाराष्ट्र का है। *(रा.प., 15.08.23)*

आदिवासी बनें विकास में भागीदार...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि जिस दिन जनजातीय समाज उन्नत हो जाएगा, भारत विश्व में विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो जाएगा। हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि अपनी संस्कृति, लोकाचार, रीति-रिवाज और प्राकृतिक परिवेश को सुरक्षित रखते हुए हमारे जनजातीय समुदाय के भाई-बहन और युवा आधुनिक विकास में भागीदार बनें।

यह बात राष्ट्रपति ने रवींद्र भवन में आयोजित 'उत्कर्ष और उन्मेष' उत्सव के शुभारंभ पर कही। उन्होंने कहा कि भारत में 700 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं और इससे दोगुना उनकी भाषाएं। सभी भारतीय भाषाओं की प्रमुख पुस्तकों का अन्य भाषाओं में अनुवाद हो, इससे भारतीय साहित्य और अधिक समृद्ध हो सकेगा।

(रा.प.,04.08.23)

महिलाएं समृद्ध तो दुनिया होगी खुशहाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब महिलाएं समृद्ध होती हैं तो दुनिया खुशहाल होती है। उनका आर्थिक सशक्तीकरण विकास को बल देता है। शिक्षा तक उनकी पहुंच वैश्विक प्रगति को प्रेरित करती है। उनका नेतृत्व समावेशिता को बढ़ावा और उनके विचार सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करते हैं।

मोदी ने महिला सशक्तीकरण पर जी-20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करते हुए कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका महिला नेतृत्व वाले विकास का दृष्टिकोण है। भारत इस दिशा में कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु एक प्रेरक उदाहरण है। साधारण जनजातीय पृष्ठभूमि से आने वाली मुर्मु सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करती है। साथ ही दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रक्षा बल की कमांडर-इन-चीफ हैं। *(रा.प., 03.08.23)*

महिला आरक्षण को मिली मंजूरी

महिला आरक्षण विधेयक 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब यह कानून बन गया है। इसका लाभ जनगणना और परिसीमन के बाद मिल सकेगा।

महिलाओं के लिए संसद व राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान वाला यह विधेयक संसद के विशेष सत्र में पारित हो गया था। लोकसभा में इसके समर्थन में 454 और विरोध में दो वोट पड़े थे। राज्यसभा में सभी 215 सांसदों ने विधेयक का समर्थन किया था। यह विधेयक 128वां संशोधन विधेयक है।

(रा.प., 30.09.23)

राजस्थान का शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन

शिक्षा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में राजस्थान ने स्कूली शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 में प्रदर्शन पर आधारित केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के 25 जिलों ने अति उत्तम श्रेणी में जगह बनाई है, जबकि मध्य प्रदेश के पांच जिले उत्तम और छत्तीसगढ़ के सिर्फ एक जिले को अति उत्तम वर्ग में स्थान मिला है।

बच्चों के सीखने की क्षमता में राजस्थान और पंजाब ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के लिए राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में 2020-21 के दौरान 742 जिलों और 2021-22 में 748 जिलों को शामिल किया गया है।

(रा.प., 12.07.23)

ग्रामीण महिलाओं ने रखी नई मिसाल

दो साल पहले कोटा जिले के सांगोद गांव की 12 महिलाओं ने एक समिति बनाकर दुग्ध संग्रहण का काम शुरू किया था। प्रदेश में आज यह महिलाओं की सहकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है। इसमें अब 25 हजार से अधिक महिलाएं हैं और 700 से भी ज्यादा गांवों से रोज 75 हजार लीटर दूध उत्पादित हो रहा है। सारा लेन-देन ऑनलाइन होता है।

इन महिलाओं के बेहतरीन उद्यमिता प्रबंधन से प्रभावित हो, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राजीविका उनकी मदद को आगे आया था और 20 मार्च 2021 को सांगोद से 'उजाला' दुग्ध उत्पादक लि. की शुरुआत की थी। संग्रहित दूध मदर डेयरी को दिया जाता है। दूध संग्रहण से लेकर प्लांट तक पहुंचाने का सारा काम महिलाएं ही करती हैं।

(दै.भा., 03.07.23)

रंग लाई लहरी बाई की कड़ी मेहनत

लहरी बाई मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले के सिलपिड़ी गांव की आदिवासी महिला किसान है। उनकी उम्र अभी 27 वर्ष है और वह श्री अन्न व पारंपरिक बीजों के संरक्षण में जुटी हैं। छोटी उम्र से ही उन्होंने कड़ी मेहनत कर मिलेट (मोटा अनाज) के विभिन्न प्रजाति के बीजों का संरक्षण का काम शुरू कर दिया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र में भी इस आदिवासी महिला किसान को मान-सम्मान मिला है। शुरू में बेगा आदिवासी समुदाय के लोग उनका काफी मजाक उड़ाते थे। लहरी बाई ने अनाज के बीजों की 150 से ज्यादा किस्मों को संरक्षित कर खुद का देशी बीज बैंक बना लिया है। वह ग्रामीणों को श्री अन्न एवं पारंपरिक फसलों की विलुप्त होती प्रजातियों के पोषक महत्व को समझाते हुए उनके संरक्षण के लिए प्रेरित कर रही हैं, साथ ही इनकी खेती को बढ़ावा भी दे रही है। *(रा.प., 01.08.23)*

सड़क सुरक्षा पर नीतिगत पैरवी के लिए राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित

'कट्स' द्वारा 25 अगस्त 2023 को केरल सड़क सुरक्षा प्राधिकरण और पर्यावरण एवं विकास केंद्र के सहयोग से तिरूवनंतपुरम में केरल सड़क सुरक्षा पर नीतिगत पैरवी के लिए राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य में गति प्रबंधन नीति और दोपहिया वाहन सुरक्षा नीति की पैरवी करना था।

इस अवसर पर 'कट्स' टीम ने केरल राज्य में जल्द ही गति प्रबंधन और दो पहिया सुरक्षा नीति लागू करने के लिए परिवहन मंत्री एंटनी राजू को नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत की। कार्यक्रम की शुरुआत में 'कट्स' के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी मधु सूदन शर्मा ने केरल सड़क सुरक्षा मुद्दों और पैरवी बिंदुओं पर विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया, जिसका मंत्री, सचिव और आयुक्त सहित सभी ने समर्थन किया।

कार्यशाला में परिवहन मंत्री एंटनी राजू ने अपने उद्बोधन में भारत के लिए सार्वभौमिक गति प्रबंधन नीति को रेखांकित करते हुए सड़कों पर गति सीमा के लिए पूरे देश के लिए एक साझा नीति का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों के उल्लंघनों से बचने के लिए भारत को छह लेन और चार लेन सड़कों, जिला सड़कों और स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित सड़कों के लिए एक सामान्य गति सीमा की आवश्यकता है।

कार्यशाला में केरल के परिवहन मंत्री, परिवहन आयुक्त, परिवहन सचिव और अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, आई.जी. ट्रैफिक, केरल सड़क सुरक्षा प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक, ट्रैफिक एस.पी., परिवहन विभाग के 35 अधिकारी और निरीक्षक, 20 इंजीनियर और यातायात अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा मीडिया प्रतिनिधियों और गैर सरकारी संगठनों के कुल 75 प्रतिभागियों ने भी कार्यशाला में भाग लिया।

राष्ट्रीय राज मार्ग पर हो रहे हैं 83 फीसदी हादसे

सरकारी आंकड़ों के अनुसार गलत दिशा में यातायात के प्रवाह के विपरीत गाड़ी चलाना भारत में तेज गति के बाद सड़क पर होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। सड़क एवं परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में 4,12,432 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1,53,972 लोग मारे गए, जबकि 3,84,448 व्यक्ति घायल हुए। रिपोर्ट के अनुसार कुल सड़क दुर्घटनाओं में से 1,28,825 दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुईं। यानी करीब 83 फीसदी हादसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुए।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में 56,007 मौत हुई, राज्य राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में 37,963 और अन्य सड़कों पर 60,002 मौते हुई। वर्ष 2021 में तेज गति से गाड़ी चलाने से 1,07,236 लोगों की मौत हुई और लाइन अनुशासन हीनता या गलत साइड के कारण 8,122 मौतें हुई। नशे में गाड़ी चलाने से 3,314 लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई और ट्रैफिक लाइट उल्लंघन के कारण 679 मौतें हुई। गाड़ी चलाते समय सेल फोन का उपयोग करने के कारण 2,982 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अन्य कारणों से 31,639 मौतें हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 18 से 45 वर्ग का आयु वर्ग दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। लगभग 67 फीसदी मौतें इसी वर्ग की हुईं।

(रा.प., 13.07.23)

सड़क हादसों से मौतों के मामले में भारत पहले नंबर पर

फिक्की और अर्नस्ट एंड यंग की रिपोर्ट में सामने आया है कि सड़क हादसों से हर साल भारत में लगभग 15 लाख लोगों की जान चली जाती है। यह वैश्विक स्तर पर ऐसी मौतों की कुल संख्या का 11 फीसदी है। दुनियाभर में हर 24 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत सड़क हादसे में चोट से हो रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1.3 अरब से अधिक मौतों और 5 करोड़ गंभीर चोटों के साथ सड़क दुर्घटना मृत्यु का 8वां बड़ा कारण है। सड़क हादसे 5 से 29 साल की उम्र के बच्चों और युवाओं की मौत की सबसे बड़ी वजह है। रोड सेफ्टी इन इंडिया-नेविगेट थ्रू नुआंसेस शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़क हादसों के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। हर साल हम एस्टोनिया देश के बराबर आबादी को सड़क हादसों में गंवा देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत ब्रासीलिया घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में शामिल है, जिसका लक्ष्य 2030 तक दुनिया में सड़क हादसों में होने वाली मौतों व घायलों की संख्या को आधा करना है। भारत में 30 फीसदी मौतों की वजह हेलमेट न पहनना जबकि 11 फीसदी मौतों की वजह सीट बेल्ट लगाने में लापरवाही है। लाल बत्ती को पार करना, मोबाइल फोन का उपयोग और गलत लेन में ड्राइविंग जैसी लापरवाही पर सख्ती से अंकुश लगाने की जरूरत है।

(रा.प., 20.07.23)

उपभोक्ता फैसले

ट्रेन में हुई चोरी तो रेलवे को करनी होगी भरपाई

ट्रेन में चोरी, लूटपाट, स्नेचिंग अथवा सामान गुम होने पर रेलवे को भरपाई करनी होगी। ऐसे मामलों में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने अहम फैसला दिया है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. इंद्रजीत सिंह ने कहा कि ट्रेन में घुसे अनधिकृत व्यक्ति द्वारा चोरी या लूटपाट की जाती है तो वारदात से यात्री को हुए नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी रेलवे की ही होगी।

मामले के अनुसार वर्ष 2016 में उमा अग्रवाल रेलवे के एसी कोच में बीकानेर से दिल्ली का सफर कर रही थी। उनके पास पर्स में कीमती सामान था। उनके रिजर्व डिब्बे में एक अनधिकृत व्यक्ति ने प्रवेश किया और उनके हाथ से जबरदस्ती वह पर्स छीनकर भाग गया। उन्होंने मामले की शिकायत रेलवे अधिकारियों को भी की।

मामले की सुनवाई नहीं होने पर हारकर उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया। मामले की सुनवाई पर आयोग ने रिजर्व डिब्बे में अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश को रेलवे की लापरवाही माना। आयोग ने रेलवे को आदेश दिया कि वह पीड़िता उमा अग्रवाल को हुई क्षति की भरपाई के रूप में 4 लाख 60 हजार रुपए मय ब्याज के अदा करे। साथ ही पीड़िता को मानसिक प्रताड़ना के तौर पर 50 हजार रुपए और केस खर्च के 10 हजार रुपए भी दें। *(दै.भा., 30.07.23)*

बीमा कंपनी उपभोक्ता को इलाज की पूरी राशि अदा करें

कोटपूतली निवासी शिवकुमार गुप्ता ने स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय में परिवाद दायर किया। उसने परिवाद में बताया कि विपक्षी स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने मेडिक्लेम पॉलिसी होते हुए भी कई शर्तों का हवाला देते हुए उनके इलाज पर खर्च हुई पूरी क्लेम राशि का भुगतान नहीं किया। उसने आयोग से बकाया राशि 98,820 रुपए दिलाए जाने की गुहार की।

जिला आयोग ने मामले की सुनवाई पर इलाज खर्च की पूरी राशि का भुगतान नहीं करने को सेवा दोष एवं अनुचित व्यापार व्यवहार करार दिया। आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी हर साल मेडिक्लेम रिन्युवल के नाम पर शर्तो को बदलती रहती है और इसकी सूचना कभी परिवादी को नहीं भी दी जाती। लेकिन क्लेम भुगतान के दौरान कंपनी अनुबंध की शर्तों का हवाला देकर उपभोक्ताओं को उनकी क्लेम राशि नहीं देती जो उनकी सेवाओं में कमी है। आयोग ने विपक्षी स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया कि वह परिवादी शिवकुमार गुप्ता को इलाज खर्च की बकाया राशि 98,820 रुपए नौ फीसदी ब्याज सहित भुगतान करे। *(दै.भा., 30.09.23)*

शुगर-फ्री मीठे उत्पादों के लेबल पर अनिवार्य हो सकती है चेतावनी

शुगर-फ्री मीठे उत्पादों के लेबल पर कंपनियों के लिए ये चेतावनी देना अनिवार्य हो सकता है कि इनमें सेहत के लिए हानिकारक तत्व है। दरअसल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) ने स्टेविया और एस्पार्टेम जैसे चीनी के वैकल्पिक उत्पादों को सेहत के लिए घातक बताया है।

> ***'रिस्ट्रिक्टिव यूज ओनली' नियम लागू करने की अपील***
>
> *कंज्यूमर वॉयस के सीओओ आशिम सान्याल ने एफएसएसएआई से डब्ल्यूएचओ की सिफारिशें स्वीकार करने और ऐसे उत्पादों पर 'रिस्ट्रिक्टिव यूज ओनली' नियम लागू करने की अपील की है।*

अंतरराष्ट्रीय संगठन ने कहा है कि इनसे टाइप-2 डायबिटीज और दिल की बीमारियां हो सकती है। इसके बाद भारतीय खाद्य नियामक (एफएसएसएआई) इस संबंध में मानक सख्त करने के लिए नई गाइडलाइंस पर विचार कर रहा है। सॉफ्ट ड्रिंक, ब्रेकफास्ट आइटम्स, कुछ खास तरह के जूस और आइसक्रीम कंपनियां अपने उत्पादों में चीनी की जगह स्टेविया और एस्पार्टेम जैसे स्वीटनर्स का इस्तेमाल कर इन्हें सेहत के लिए अच्छे विकल्प के तौर पर प्रचारित करती हैं।

खाद्य नियामक इस ट्रेंड पर लगाम कस सकता है। इंडियन डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष आरएस सोढ़ी का कहना है कि यदि एफएसएसएआई बिना चीनी वाले मीठे उत्पादों के लेबल पर चेतावनी का उल्लेख करने के लिए कहता है तो यह निश्चित रूप से शुगर-फ्री उत्पादों और ड्रिंक्स की खपत को प्रभावित करेगा। अब ग्राहक लेबल को संजीदगी से लेते हैं। *(दै.भा., 23.06.23)*

प्रदीप एस. महता बी.डब्लू. सोशल इम्पैक्ट अवॉर्ड से सम्मानित

नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अग्रणी सार्वजनिक नीति अनुसंधान, पैरवी और नेटवर्किंग गैर सरकारी संगठन 'कट्स' इंटरनेशनल के महामंत्री प्रदीप एस. महता को प्रतिष्ठित बी.डब्लू. सोशल इम्पैक्ट अवॉर्ड 2023 से सम्मानित किया गया।

यह पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ठ योगदान, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और सामाजिक आवश्यकताओं का समाधान करने जैसे कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेकर समाज के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए उनके समर्पण को मान्यता देता है।

इस मौके पर उन्होंने संगठन के अभियान 'इनोवेटिव फाइनेंस फॉर क्लाइमेट प्लेनेट' पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता से होने वाले नुकसान के हानिकारक प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से एक बड़ा कोष स्थापित करने की पहल की गई है। ऐसा करके हम मानवता के लिए बेहतर भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं।

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत, रा.दू.: राष्ट्रदूत

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.228 2821
फैक्सः 228 2485, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
यहां भी दिल्ली, कोलकता और चित्तौड़गढ़ (भारत); लुसाका (जाम्बिया); नैराबी (केन्या); आक्करा (घाना); हनोई (वियतनाम); जिनेवा (स्विटजरलैंड) और वॉशिंगटन डी.सी. (यूएसए)